

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 17 जनवरी, 2025

**संख्या का०आ०४/पं०अ०१८/१९६१/धा०१५/२०२५.**— पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं ।
2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 में, उप-नियम (4) का लोप कर दिया जाएगा ।
3. उक्त नियमों में, नियम 15 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"15क. पंचायत को भुगतानयोग्य राशि अवधारित करने के सिद्धांत और रीतियां. [धारा 3 (2) iii].—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 2 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (ii-ख) और धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (iii) के अधीन शामलात देह के दायरे में भूमि के स्वामित्व का दावा करने का हकदार है, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से बारह मास की अवधि के भीतर उसके द्वारा पंचायत को भुगतानयोग्य राशि के अवधारण के लिए कलक्टर को आवेदन कर सकता है:

परन्तु कलक्टर, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण से बारह मास के भीतर आवेदन दायर करने से रोका गया था, तो बारह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन ले सकता है।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर पंचायत को नोटिस जारी करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद तथा ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाए, करने के बाद आवेदक द्वारा पंचायत को भुगतानयोग्य राशि का अवधारण करेगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (ii-ख) के अधीन शामलात देह के दायरे में भूमि के स्वामित्व का दावा करने का हकदार पाया जाता है, तो वह पंचायत को प्रचलित सर्कल कलक्टर दर के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु ऐसी राशि का भुगतान बीस बराबर वार्षिक किस्तों में सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ किया जा सकता है।

15ख. बाजार दर अवधारित करने की रीति. [धारा 5क(1क)].— (1) कोई व्यक्ति जो धारा 5क की उपधारा (1क) के उपबधों के अधीन आने वाली भूमि को खरीदने का हकदार है, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से बारह मास की अवधि के भीतर उक्त भूमि की खरीद के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकता है:

परन्तु यदि आवेदक को पर्याप्त कारण से बारह माह के भीतर ऐसा आवेदन करने से रोका गया हो, तो अनधिकृत कब्जे वाली भूमि की खरीद के लिए आवेदन, उक्त बारह मास की अवधि की समाप्ति के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है।

(2) (i) इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से बारह मास के भीतर किए गए आवेदन के लिए भूमि की बाजार दर, 31 मार्च, 2004 को प्रचलित कलक्टर दर के डेढ़ गुना के बराबर होगी:

परन्तु यदि 31 मार्च, 2004 को प्रचलित कलक्टर दर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं पाई जाती है, तो आगामी वर्ष या ऐसे आगामी पश्चातवर्ती वर्ष जिसके लिए कलक्टर दर उपलब्ध है, के दौरान प्रचलित कलक्टर दर को बाजार दर निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

(ii) उपरोक्त उप-नियम (2)(i) के परन्तुक के अधीन किए गए आवेदन के लिए भूमि की बाजार दर कलक्टर दर, जो आवेदन की तिथि से बीस वर्ष पूर्व प्रचलित थी, के डेढ़ गुना के बराबर होगी तथा यदि उस वर्ष की कलक्टर दर उपलब्ध नहीं है, तो आगामी वर्ष, जिसके लिए कलक्टर दर उपलब्ध है, के दौरान प्रचलित कलक्टर दर।"

अमित कुमार अग्रवाल,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT**

**Notification**

The 17th January, 2025

**No. S.O.4/P.A.18/1961/S.15/2025.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2025.
2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 (hereinafter called to as the said rules), in rule 12, sub-rule (4) shall be omitted.
3. In the said rules, after rule 15, the following rules shall be added, namely:-

**“15A. Principle and manner for determining amount payable to Panchayat. section 3(2)(iii). – (1)**  
A person, who is entitled to claim the ownership of land within the ambit of shamilat deh under sub-clause (ii-b) of clause (g) of section 2 and sub-clause (iii) of sub-section (2) of section 3, may, within a period of twelve months from the date of publication of these rules, apply to the Collector for the determination of the amount payable to the Panchayat by him:

Provided that the Collector may entertain the application even after the expiry of the said period of twelve months, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the application within twelve months.

(2) On receipt of an application, the Collector shall issue notice to the Panchayat and after giving an opportunity of being heard and after making such enquiry as may be considered necessary, shall determine the amount payable by the applicant to the Panchayat.

(3) Where a person is found entitled to claim the ownership of land within the ambit of shamilat deh under sub-clause (ii-b) of clause (g) of section 2, he shall be liable to pay an amount equal to fifty percent of the prevalent circle Collector rate to the Panchayat:

Provided that the payment of such amount may be made in twenty equal annual installments alongwith seven percent simple interest.

**15B. Manner of determining market rate section 5A(1A).** (1) A person who is entitled to purchase the land covered under the provision of sub-section (1A) of section 5A, may, within a period of twelve months from the date of publication of these rules, apply to the Gram Panchayat for purchase of said land:

Provided that the application for purchase of the unauthorized occupied land may be entertained even after the expiry of said period of twelve months, if the applicant was prevented by sufficient cause from making such application within twelve months.

(2)(i) For application made within twelve months from the date of publication of these rules, the market rate of the land shall be equal to one and half times of the Collector rate prevalent as on the 31st March, 2004

Provided that if Collector rate prevalent as on the 31st March, 2004 is not found available in the record, the Collector rate prevalent during the next year or such next subsequent year for which Collector rate is available, shall be considered the market rate.

(ii) For application made under the proviso to sub-rule(2)(i) above, the market rate of the land shall be equal to one and half times of the Collector rate that was prevalent twenty years prior to the date of application and if the Collector rate of that year is not available, the Collector rate prevalent during the next year, for which Collector rate is available.”.

AMIT KUMAR AGRAWAL,  
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Development and Panchayats Department.